ADFACTORS PR
Knowledge-driven communications

HMC 2013 Curtain Raiser (Delhi)

NEWS COVERAGE

Publication : Amar Ujala

Edition : New Delhi

Date : 23-11-13

भारी खनिज खनन नीति में हो सुधार

नई दिल्ली। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारी खनिजों के खनन के लिए नीतियों में सुधार की मांग की है। इंटरनेशनल हैवी मिनरल्स सम्मलेन में एसोसिएशन ने कहा कि खनिज संसाधनों के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए। खनिज युक्त वन भूमि को खनिज भूमि घोषित किया जाए और भूमि, वन, वायु एवं जल अधिनियमों की तरह खनिज भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए कानून बने।

Publication : Jansatta

Edition : New Delhi

Date : 23-11-13

खनन के लिए नीतियों में सुधार की मांग

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 22 नवंबर। खनिज उद्योग ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारी खनिजों के खनन के लिए नीतियों में सुधार किया जाए। माइनिंग इंजीनियरों की संस्था- माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हेवी मिनरल कांफ्रेंस- 2013 के आयोजन का एलान करते हुए यह मांग की। वाइजाग में आयोजित इस सम्मेलन का विषय होगा 'ओवरकमिंग न्यू चैलेंजेज'। देश में आयोजित यह पहला सम्मेलन होगा जिसमें सभी प्रमुख हेवी मिनरल माइनिंग देशों (भारी खनिजों का खनन करने वाले देश) जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, वियतनाम, श्रीलंका, यूरोप और भारत से 275 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

खनन उद्योग के सामने आने वाली कई चुनौतियों की वजह से इस सेक्टर को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। एसोसिएशन चाहती है कि खनन के लिए वन अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जल, वायु अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण की जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाए। साथ ही खनिज युक्त भूमि के संरक्षण के लिए खनन पट्टों का अनुदान प्राप्त हो सके ताकि ऐसी भूमि के अतिक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। वजह इस भूमि का गैर-खनन के लिए इस्तेमाल करने से संसाधनों की उपयोगिता कम होती जा रही है। संघ के अध्यक्ष अरजेथ बागची ने कहा कि खनन इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास व विनिर्माण उद्योग का आधार है। खनन के बिना ये सभी उद्योग भी नहीं रहेंगे। अगर सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना है और समग्र विकास को बढ़ावा देना है तो खनन क्षेत्र की इन सभी चुनौतियों का समाधान करना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र पर्याप्त खनिज आपूर्ति के बिना बाधित हो जाएगा।

एसोसिएशन चाहती है कि सरकार भारी खनिज खनन को खनिज रेत खनन का नाम दे। वर्तमान में सरकार इसके लिए 'समुद्र तटीय रेत खनन' का नाम देती है। जो सही नहीं है क्योंकि खनन से मात्र 10-15 फीसद ही प्रमुख खनिजों का निष्कर्षण होता है। शेष 85-90 फीसद रेत (माइनर मिनरल) होती है। जिसका उपयोग उन खनिज क्षेत्रों की बहाली के लिए किया जाता है जहां सौ फीसद रेत का उपयोग माइनर मिनरल के रूप में किया जाता है।

Publication : Mahamedha

Edition : New Delhi

Date : 03-12-13

अंतरराष्ट्रीय भारी खनिज सम्मेलन कल से

नई दिल्ली (ए)। देश में माइनिंग इंजीनियरों की राष्ट्रीय संस्था माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नौंवे अंतरराष्ट्रीय भारी खनिज सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की।

संस्था ने बताया कि 27 से 29 नवंबर को विजाग में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देश में आयोजित अपनी तरह के पहले सम्मेलन में भारी खनिज संसाधन वाले देशों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, वियतनाम, श्रीलंका, अमेरिका के 275 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

इस सम्मेलन के माध्यम से भूमि अधिग्रहण एवं खनन पट्टों के अनुदान को मंजूरी दिए जाने, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की तरह खनिज संसाधनों के लिए भी कानून बनाए जाने सहित भूमि, जल एवं वायु की ही तरह खनिज भूमि पर अतिक्रमण रोकन के लिए काननू बनाने की मांग की जाएगी। इसमें खनन क्षेत्र से जुड़ी तकनीकी और प्रबंधकीय चुनौतियों के साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों और इसके कारोबार में आनेवाली समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

Publication : Business Bhaskar

Edition : New Delhi

Date : 03-11-13

हेवी मिनरल्स कॉन्फ्रेंस की घोषणा

नई दिल्ली • 5000 माइनिंग इंजीनियरों की राष्ट्रीय संस्था, माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने 9वें इंटरनेशनल हेवी मिनरल कॉन्फ्रेंस-2013 के आयोजन की घोषणा की। विजाग में 27 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित की जाने वाले इस सम्मेलन का विषय 'ओवरकमिंग न्यू चैलेंजेस' रखा गया है। सम्मेलन में सभी प्रमुख हेवी मिनरल माइनिंग देशों (भारी खनिजों का खनन करने वाले देश) जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य, चीन, वियतनाम, श्रीलंका, यूरोप और भारत से 275 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। दुनिया भर से आए ये प्रतिनिधि माइनिंग सेक्टर से जुड़ी तकनीकी, प्रबंधकीय चुनौतियों एवं इस सेक्टर में मौजूद अवसरों तथा इसके कारोबार में आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे। एमएमआरडी अधिनियम के अनुसार निर्धारित भारी खनिजों जैसे इलमेनाईट, रूटाइल, जिरकॉन, गार्नेट, सिलिमेनाइट एवं मोनेजाइट आदि सभी को इसके तहत कवर किया जाएगा।

Publication : Political and Business Daily

Edition : New Delhi

Date : 22-11-13

MEAI president Arjeth Bagchhi and Delhi chapter chairman BB Dhar at a conference of 9th International Heavy Minerals conference, in New Delhi —PBD photo by Amit Shrivastava

Mining industry seeks policy reforms for heavy minerals

PBD BUREAU

NEW DELHI, NOV 21

THE Mining Engineers' Association of India (MEAI) has sought policy reforms for mining heavy minerals in the country including opening up of Monazite mining by Private Sector and De-notification of forest lands bearing Minerals and declare them as "Mineral bearing land" available for Mining.

The industry also announced IXth international conference on Heavy Mineral Mining at Vizag from November 27-29.

This HMC-2013 is the first in the country and will host over 275 delegates from all major Heavy Mineral Mining countries like Australia, Canada, Africa, US, china, Vietnam, Sri lanka, Europe, India etcdiscussing the technical, Managerial & Business challenges & opportunities facing the sectorworld wide.

The following major minerals as per the MMRD Act together called heavy minerals will be covered vizIlmenite, Rutile, Zircon, Garnet, Sillimanite and Monazite.

The industry said that better policy environment will help boost resource to production ratio from an abysmal low of 0.001 per cent to 0.01 per cent.

Talking to reporters here today, Arjeth Bagchhi, MEAI President said, "Mining is oxygen to the infrastructure, housing and manufacturing industry. Without mining, infrastructure, housing, manufacturing and even service sector cannot survive. If GDP has to increase and inclusive growth has to happen, mining has to overcome all challenges and grow in a big way."

TV Chowdhary, Former president MEAI and director Trimex said our deposits are of high grade and found in huge quantities.

"Despite India being amongst top few countries in terms of resource availability, it is amongst the last few in production. It is an irony that in spite of such large resources, even the indigenous requirement of around 1,70,000 tonne per annum (TPA) of TiO2 is not fully met. In fact 1,00,000 t a major quantity is imported at present."

The industry claims that the mining for heavy mineral and allied activities are prima-facie devoid of the normal sources of the pollution attributed to most of the projects and industries.

India must have its own Short, Medium and Long term Road Map for Mineral and Land resource Security and access to sufficient, reliable, affordable and sustainable supplies of Minerals, the industry suggested.

Publication : The Pioneer

Edition : New Delhi

Date : 22-11-13

MEAI announces IXth international conference on Heavy Mineral Mining

NEW DELHI: Mining Engineers' Association of India on Thursday announced the IXth international Heavy Minerals Conference - 2013 with the theme "Overcoming New Challenges" to be held at Vizag. This HMC-2013 is the first in the country and will host over 275 delegates from all major Heavy Mineral Mining countries like Australia, Canada, Africa, US, china, Vietnam, Sri lanka, Europe, India etc discussing the technical, Managerial & Business challenges & opportunities facing the sector world wide. **PNS**

Publication : Economic Times
Link : http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-11-21/news/44326797_1_monazite-rutile-illegal-mining

Allow private sector in Monazite mining, ease rules: MEAI

PTI Nov 21, 2013, 08.10PM IST

Tags:

- Indian Rare Earths Ltd
- Association of India President Arjeth Bagchhi
- Arjeth Bagchhi

NEW DELHI: The government should allow private sector in mining of Monazite, which is the primary source of radio-active thorium, and ease rules and regulations to increase its production, an industry body of mining engineers today said.

Thorium, a strategic metal, is an integral part of India's three-stage nuclear power programme.

The government should also relax rules and regulations for mining of other heavy minerals -- Ilmenite, Rutile, Zircon, Garnet and Sillimanite -- and provide time bound clearances for increasing their production, the Mining Engineers' Association of India President Arjeth Bagchhi said here.

"India's production of these heavy minerals are meagre compared to the vast reserves and resources available in the country. Government needs to resolve issues related to land acquisition, energy, water and environment. The Beach Sand Policy of 1998 also needs to be amended," he told reporters.

The six minerals are also known as beach sand minerals. Of them, India has large reserves of Ilmenite (through which Titanium is extracted), Rutile, Zircon, Garnet and Monazite.

Currently only Indian Rare Earths Ltd (IREL), a PSU under Department of Atomic Energy, has the permission for commercial exploitation of Monazite and thorium deposits in the country. As per official data, India's has 11.93 million tonnes (MT) Monazite reserves, largest in the world. Production figures of Thorium are not available due to its strategic importance.

"There is no logic behind not allowing Monazite mining by private sector, it is a national waste. It can bring mind boggling benefits to the society, if companies other than IREL are allowed in the sector. Private sector is already engaged in its production in many other countries," MEAI's former President T V Chowdary said.

The MEAI is hosting ninth edition of the International Heavy Minerals Conference in Vizag next week, which will highlight various issues related to the sector.

Seeking faster clearances for mining beach sand minerals like Ilmenite, Chowdary said that over 80 per cent of sand is thrown back on the beaches after extraction of the minerals and is should not be confused with illegal mining of sand along the rivers.

"Beach sands can't be used for construction purposes... Clearances should take 9-10 months. Lessening the tiers and quickening the clearances would help us in increasing production of heavy minerals," he said.

He also claimed that land acquisition policy for the beach sand mining should be eased as "unlike other minerals, land is given back to the original owners only after 2-3 years, when mining is complete in the area".

India has over 500 million tonnes (MT) of Ilmenite reserves and resources, while production is only about 8 lakh tonnes annually. For zircon, annual domestic production is 35,000 tonnes, while the resource base is over 32 MT. The six heavy minerals are primarily found in 5 states -- Odisha, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Maharashtra.